

प्रेषक,

आर. के. सुधांशु,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,

श्रीनगर (गढ़वाल)।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 03 अक्टूबर, 2015

विषय: प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवसृजित 21राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 'नाबार्ड' से वित्त पोषण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में पी.एल.ए. में रखी गई धनराशि के आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 209/XLI-1/2015-39/2014 दिनांक 26.3.2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा नवसृजित 21पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई-1, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आगणन 12163.08लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 11770.47 लाख (₹ 1002.41लाख सिविल कार्य+₹ 10768.06लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार अधिप्राप्ति) की 'नाबार्ड' से वित्त पोषण के उपरान्त प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 3531.14लाख (₹ पैतीस करोड़ इकत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) की वित्तीय एवं नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. दिनांक 09.01.2015 एवं दिनांक 05.02.2015 को 'नाबार्ड' से वित्त पोषित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु सम्पन्न व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित पॉलीटेक्निक अनावासीय भवन प्रीइन्जीनियर्ड भवन तकनीक से दो ट्रेड संचालन हेतु निर्मित किये जाएंगे।

3. तदोपरान्त आपके पत्र संख्या 1185/नि.प्रा.शि./प्लान-छ:-123नाबार्ड/2014-15 दिनांक 27.3.2015 के द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या 242/XLI-1/2015-39/2014 दिनांक 26.3.2015 द्वारा, उक्त शासनादेश दिनांक 26.3.2015 द्वारा निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 2500लाख को भूमियुक्त 05पॉलीटेक्निकों यथा, बांसबगड़, चिन्यालीसौड़, मल्लासालम, बछेलीखाल, बाजपुर फेस-2 के अनावासीय निर्माण कार्य हेतु आहरित कर व्यय करने तथा शेष ₹ 1031.14लाख को जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी के पी.एल.ए. में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. इस संबंध में आपके पत्र संख्या 2055/नि.प्रा.शि./लेखा-बजट/2015-16 दिनांक 12.8.2015 के द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.3.2015 एवं शासनादेश दिनांक 30.3.2015 के माध्यम से पी.एल.ए. में रखी गई धनराशि ₹ 1031.14लाख (₹ दस करोड़ इकत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) को अन्य 05राजकीय पॉलीटेक्निकों यथा, बेरीनाग (पिथौरागढ़), चम्पावत, जैती (अल्मोड़ा), पिपली (उत्तरकाशी), बांस (पिथौरागढ़) के अनावासीय भवन निर्माण कार्य हेतु पी.एल.ए. से आहरित कर नियमानुसार व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमशः....

5. यदि शासनादेश दिनांक 26.3.2015 एवं शासनादेश दिनांक 30.3.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि को कार्यदायी संस्था द्वारा बैंक खाते में रखा गया हो तो उक्त धनराशि पर अद्यतन अर्जित व्याज का विवरण उपलब्ध कराने पर ही अग्रेतर धनराशि की स्वीकृति निर्गत की जाएगी।
6. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.3.2015 एवं शासनादेश दिनांक 30.3.2015 के अनुसार यथावत लागू होंगे।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :209(पी)/XXVII(3)/2015-16 दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर. के. सुधांशु)
सचिव।

संख्या 1090 (1)/XLI(1)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. उपमहाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राजपुर रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित जिलाधिकारी।
6. कोषाधिकारी, पौड़ी/श्रीनगर।
7. परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई-1, देहरादून।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
11. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।